

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1527
09 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएँ

1527. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश भर में कार्यशील गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की राज्य-वार और विशेषकर आंध्र प्रदेश के तट पर, कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में संचालित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हाँ, तो देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी विकास के लिए प्रस्तावित, विचाराधीन और वर्तमान में कार्यान्वित पहलों, योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत पाँच वर्षों के दौरान, विशेषकर आंध्र प्रदेश में ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार ने भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के उपयोग और संचालन के संबंधी में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी, विशेषकर आंध्र प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार के पास ओडिशा में, विशेषकर भद्रक और बालासोर जिलों में, सहकारी नेतृत्व वाली गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की पहल, मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों (एफपीपीओ) की सहायता और समुद्री अवसंरचना के विकास को बढ़ाने या प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं और वित्तपोषण तथा प्रस्तावित किए जाने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (छ): भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य संसाधनों की संभावित उपज के पुनर्वैधीकरण (री-वैलिडेशन) के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अनुमान के अनुसार, भारत के EEZ में मत्स्य संसाधनों की प्रति वर्ष संभावित उपज (PY) 53.1 लाख टन है, जिसमें ओशेनिक/गहरे समुद्र के संसाधनों (500 मीटर से अधिक गहराई वाले क्षेत्र) की संभावित उपज 2.31 लाख टन शामिल है। वर्तमान में भारत, डीप-सी मात्स्यिकी संसाधनों सहित समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का 44.95 लाख टन (2023-24) उपयोग कर रहा है। यह उत्पादन भारतीय EEZ में उपलब्ध 53.1 लाख टन समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों की संभावित उपज से कम है। नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज़, 2017 में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ डीप-सी फिशिंग को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने हेतु पारंपरिक मछुआरों के कौशल एवं क्षमता संवर्धन, मछुआरा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वदेशी डीप-सी फिशिंग वेसल्स की शुरुआत, ऑन-बोर्ड प्रशिक्षण तथा बाजार एवं निर्यात से जुड़ाव हेतु नई योजनाएँ प्रारंभ करने की परिकल्पना की गई है। भारतीय EEZ और हाई सी में डीप-सी फिशरी रिसोर्स के दोहन की संभावनाओं तथा नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज़, 2017 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने मार्च 2017 में 'ब्लू रेवोल्यूशन' पर आधारित अपनी केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के तहत पारंपरिक मछुआरों को डीप-सी फिशिंग वेसल्स (DSFVs) के अधिग्रहण में सहायता प्रदान करने हेतु एक उप-घटक प्रारंभ किया।

डीप सी फिशिंग वेसल्स (DSFVs) के अधिग्रहण के लिए पारंपरिक मछुआरों को वित्तीय सहायता भी 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) के तहत सामान्य श्रेणी के लिए 40% सब्सिडी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला लाभार्थियों के लिए 60% सब्सिडी की दर से जारी रखी गई है। DSFVs के लिए सहायता मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) के तहत भी प्रदान की जाती है। ब्लू रेवोल्यूशन(नीली क्रांति), PMMSY, और FIDF की योजनाओं के तहत, पारंपरिक मछुआरों द्वारा 1243 डीएसएफवी खरीदने और निर्यात क्षमता के लिए 1330 मौजूदा फिशिंग वेसल्स के अपग्रेडेशन या बदलने के लिए कुल 895.9 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। आंध्र प्रदेश सहित मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के तहत DSFV के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

पीएमएमएसवाई की केंद्रीय क्षेत्र योजना में "ट्रेनिंग, अवेयरनेस, एक्सपोजर और कैपेसिटी बिल्डिंग " घटक के अंतर्गत, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) को प्रशिक्षण घटक को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। प्रशिक्षण घटक में आंध्र प्रदेश राज्य सहित सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मछुआरों, मत्स्य किसानों, मत्स्य श्रमिकों/विक्रेताओं और मात्स्यिकी विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने, जागरूक करने, एक्सपोजर और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस घटक के अंतर्गत, केंद्रीय मात्स्यिकी नौवहन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (CIFNET) और MPEDA-नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग (NETFISH) के सहयोग से एनएफबीडी द्वारा डीप सी फिशिंग और ऑन-बोर्ड फिश हैंडलिंग पर समुद्री मछुआरों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, ओशनिक टूना फिशरी में भारत की क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 2705 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया है।

भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य समेत तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारंपरिक मछुआरों को जागरूक करने और उनकी कौशल विकास के लिए पहल की है। ब्लू रेवोल्यूशन और PMMSY योजनाओं के तहत NFDB ने CIFNET के साथ मिलकर डीप सी फिशिंग ऑपरेशन में क्षमता निर्माण और टूना की ऑनबोर्ड हैंडलिंग पर प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 5200 पारंपरिक मछुआरों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार "होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच" को अपनाकर, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है, जिसका उद्देश्य डीप सी फिशिंग, वैल्यू-चेन, प्रोसेसिंग और निर्यात में लघु स्तरीय मछुआरों को बढ़ावा देना है। सहकारिता मंत्रालय सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करके और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) के माध्यम से सहकारी ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर इस पहल को सपोर्ट करता है। यह फिशिंग फ्लीट के आधुनिकीकरण, सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा देने, वैल्यू चेन में सुधार और मछुआरों की आय में वृद्धि करके मछुआरा समुदाय के विकास पर केंद्रित है। ऐसी सहकारी समितियों के सुदृढीकरण के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और सहकारी समितियों को ऋण नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NCDC) के माध्यम से प्रदान की जाती है। सरकार ओडिशा राज्य सहित सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीप सी फिशिंग गतिविधियों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से लगी हुई है।

डीप सी फिशिंग वेसल्स के संबंध में 9 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1527 के उत्तर में उल्लिखित विवरण - आंध्र प्रदेश राज्य सहित भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत फिशिंग वेसल्स की राज्यवार संख्या और आवंटित निधि :

(i) वित्त वर्ष 2017-20 के दौरान नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन पर केन्द्र प्रायोजित योजना के उपघटक "डीप सी फिशिंग वेसल्स के लिए सहायता" के तहत स्वीकृत डीप सी फिशिंग वेसल्स का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्रम.सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	डीप सी फिशिंग बोट्स (संख्या)	कुल परियोजना लागत (रुपए लाख में)	भारत सरकार द्वारा जारी निधि (रुपए लाख में)
1.	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	02	160.00	32.95
2.	आंध्र प्रदेश	12	960.00	233.28
3.	दमन और दीव	05	400.00	144.00
4.	गुजरात	145	11,600.00	2610.88
5.	ओडिशा	04	320.00	38.40
6.	तमिलनाडु	750	60,000.00	28,150.00
	कुल	918	73,440.00	31209.51

(ii) वर्ष 2018-20 के दौरान नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन पर केन्द्र प्रायोजित योजना के उपघटक "ट्रॉलरों को संसाधन विशिष्ट डीप सी फिशिंग वेसल्स में परिवर्तित करना" के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार जारी फंड:

(रु. लाख में)

क्रम संख्या	राज्य	अपग्रेड करने के लिए वेसल्स (संख्या)	कुल परियोजना लागत (रुपए लाख में)	भारत सरकार द्वारा जारी निधि (रुपए लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	57	855.00	427.50

(iii) 2020-25 (अब तक) के दौरान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के उपघटक "पारंपरिक मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग वेसल्स के अधिग्रहण के लिए सहायता" के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत परियोजनाएं

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	डीप सी फिशिंग बोट्स (संख्या)	कुल अनुमानित लागत (रुपए लाख में)	भारत सरकार का शेयर (रुपए लाख में)
1.	अंडमान और निकोबार	6	720.00	336.00
2.	आंध्र प्रदेश	50	6000.00	1526.40
3.	गुजरात	50	6000.00	1857.6
4.	कर्नाटक	114	13680.00	3542.40
5.	केरल	20	2400.00	576.00
6.	लक्षद्वीप	10	1200.00	720.00
7.	महाराष्ट्र	63	7560.00	2491.20
8.	पुदुच्चेरी	9	1080.00	600.00
कुल		322	38640	11649.6

(iv) 2020-25 के दौरान (अब तक) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के उपघटक "निर्यात क्षमताओं के लिए मौजूदा फिशिंग वेसल्स का को अपग्रेड करना" के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी फंड

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	डीप सी फिशिंग बोट्स (संख्या)	कुल अनुमानित लागत (रुपए लाख में)	भारत सरकार का शेयर (रुपए लाख में)
1	अंडमान और निकोबार	10	150	66
2	गुजरात	925	13875	3690
3	गोवा	60	900	248.40
4	कर्नाटक	15	225	66.6
5	लक्षद्वीप	70	344.63	206.78
6	महाराष्ट्र	40	600	171
7	ओडिशा	100	1500	450
8	पश्चिम बंगाल	53	795	214.2
कुल		1273	18389.63	5112.98